

## अल्पविकास का आश्रयता सिद्धांत

### इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 आश्रयता सिद्धांत की शुरूआत
- 9.3 आश्रयता सिद्धांत का विस्तार: गंडर फ्रैंक और वालरस्टेन
- 9.4 आश्रयता सिद्धांत की अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियाँ
- 9.5 आश्रयता सिद्धांत की समीक्षा
- 9.6 आश्रयता सिद्धांत की प्रासंगिकता
- 9.7 सारांश
- 9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

### अधिगम उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्नलिखित का आलोचानत्मक विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे:

- आश्रयता सिद्धांतों का योगदान;
- अधिक निर्धन राष्ट्रों के स्पष्टोच्चारण के रूप में आश्रयता सिद्धांत; और
- आश्रयता सिद्धांत की प्रासंगिकता और समीक्षा।

### 9.1 प्रस्तावना

खंड II की इकाईयों ने हमें विकास पर आधारित विविध परिप्रेक्ष्यों से अवगत कराया जैसे कि आधुनिकीकरण सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और विकास पर मार्क्सवादी एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। आइए अब ऐसे सिद्धांत की ओर रुख करें जिनकी उत्पत्ति विकास के वृद्धि माडलों पर एक प्रतिक्रिया के रूप में की गई। मौजूदा इकाई आश्रयता सिद्धांत से संबंधित है जिसे पश्चिमी उन्मुख विकास मंडलों की समीक्षा के रूप में विकसित किया गया। आश्रयता सिद्धांत जो कि तृतीय विश्व और इसके साथ-साथ प्रथम विश्व के बहुत से बुद्धिजीवियों द्वारा विकसित विचारों का पुंज है, इनके अनुसार धनी राष्ट्रों ने अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए अधिक निर्धन राष्ट्रों का सहारा लिया। आश्रयता सिद्धांत तीसरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य से समृद्ध राष्ट्रों की समीक्षा है। सिद्धांत के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं जो इसे समीक्षा का रूप देते हैं। आश्रयता सिद्धांत की हम तीन लड़ियों की प्रस्तुति करेंगे, केंद्र एवं परिधि प्रतिक्रिया, रॉल प्रेबिश द्वारा और आन्द्रे गंडर फ्रैंक के विचार और इमैनुअल वालरस्टेन का विश्व व्यवस्था का सिद्धांत हम ऐसे निहितार्थों के लिए भी आश्रयता सिद्धांतों की जांच करेंगे जो कि तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि क्या उत्तर के समृद्ध राष्ट्रों और दक्षिण के निर्धन राष्ट्रों के बीच की आर्थिक असमानता को प्रस्तुत करने में ऐसे सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता है भी या नहीं।

### 9.2 आश्रयता सिद्धांत की शुरूआत

आश्रयता सिद्धांत अनिवार्यता विकास के नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होता है जिसने विकास और वृद्धि को बराबर का महत्त्व दिया। (उदारवादी परिप्रेक्ष्य और वृद्धि एवं प्रगति के विचार पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए इकाई 1 और इकाई 6 देखें)

विकास के वृद्धि मॉडल का अनुसरण करने वाले राष्ट्र अमीर राष्ट्र थे और सभी निर्धन राष्ट्र जो पकड़ बनाना चाहते थे, उन्होंने इन राष्ट्रों की बराबरी करने की चेष्टा की। वृद्धि मॉडल से निर्धन देशों को वांछित परिणाम नहीं दिया, लेकिन इससे जो हुआ वह था कि इसमें निर्धन और धनी राष्ट्रों के बीच की असमानताएं अधिक विस्तृत होती गईं। रॉल प्रेबिश द्वारा किए गए शोध के अनुसार समृद्ध राष्ट्रों की संपदा में जब बढ़ोतरी हुई तब निर्धन राष्ट्रों की संपदा में घटोतरी हो गई।

1960 और 1970 के बीच के समय में आश्रयता सिद्धांत काफी लोकप्रिय था इसे रॉल प्रेबिश द्वारा विकसित किया गया जो कि 1950 में लेटिन अमेरिका के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के निदेशक थे। इस सिद्धांत को विविध लड़ियों में विकसित किया गया जिसे रॉल के बाद आन्द्रे गंडर फ्रैंक ने अपने ढंग से मार्क्सवाद के रूप में इसे विकसित किया और इमैन्युअल वालरस्टेन ने इसे पुनः परिभाषित किया और इसे 'विश्व व्यवस्था' कह कर पुकारा। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था आश्रयता सिद्धांतवादी दावा करते हैं कि उच्च औद्योगिकृत देशों में होने वाली आर्थिक वृद्धि से अनिवार्य रूप से निर्धन देशों में वृद्धि नहीं हुई।

### बॉक्स 9.1: रॉल प्रेबिश

रॉल प्रेबिश का जन्म अर्जेन्टाइना में हुआ था। उन्होंने ब्यूनस'आयरस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और बाद में इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य भी किया। प्रेबिश ने किन्स के नवक्लासिकी अर्थिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जिसके अनुसार अधिक निवेश और उपभोग से आर्थिक गतिविधि की रफ्तार बढ़ती है। 1900 के आरंभ के वर्षों में गोमांस और गेहूँ के निर्यात के साथ अर्जेन्टाइना की आर्थिक वृद्धि द्वारा प्रेबिश के विचारों को बढ़ावा मिला। हालांकि 1930 की मंदी के बाद अर्थव्यवस्था चरम मंदी पर पहुंच गई जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया और इसी वजह से अर्जेन्टाइना की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। इस बदलाव ने प्रेबिश को नव क्लासिकी सिद्धांतों की पुनः जांच की ओर अग्रसर किया। तत्पश्चात् उसने व्यापार और सत्ता के ढांचों के व्यावहारिक पहलुओं से अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक पहलुओं को अलग करके देखना शुरू किया। अर्जेन्टाइना सेंटर बैंक के अध्यक्ष होने के नाते उसने गौर किया कि चरम मंदी के दौरान प्राथमिक उत्पादों जैसे कि कृषि वस्तुओं के मूल्य विनिर्मित गौण उत्पादों के मूल्यों की तुलना में काफी घट गए। हालांकि वह और उसके साथीगण इस असमानता के लिए जिम्मेवार सही तंत्र को स्पष्ट करने के योग्य नहीं थे, बावजूद यह गौर करने के कि प्राथमिक और गौण वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी दशाओं में काफी फर्क था। जहां कृषक वसूली जाने वाली कीमत पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक वर्ष समान मात्रा में फसल बोते थे वहीं विनिर्माता मांग के प्रत्याशित परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अपनी क्षमता को कम करने या बढ़ाने के योग्य थे। उन्होंने इस विचार को आगे और अधिक विकसित किया जब वे लेटिन अमेरिका आर्थिक आयोग (ई सी एल ए) के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र रूप अमेरिका जैसे केंद्रों को लेटिन अमेरिकी जैसी इर्द-गिर्द के देशों ने किस प्रकार प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति की, इस पर जर्मन अर्थशास्त्री हंस सिंगर का भी समान निष्कर्ष था। उनकी प्रतिज्ञा को सिंगर-प्रेबिश शोध कहते हैं (स्रोत: [http : 11 en. wikipedia. org/wiki/Raul Prebisch](http://11.en.wikipedia.org/wiki/Raul_Prebisch)) ।

प्रेबिश के अर्जेन्टाइना की अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रेक्षण ने एक ऐसी अभिधारणा को दर्शाया जिसने अनिवार्यतया विश्व को केंद्र और परिधि जैसी संकल्पना में विभाजित कर दिया। यद्यपि उसके प्रेक्षण, लेटिन अमेरिका में उसके अनुभवों पर आधारित थे फिर भी उन्हें ऐसे सभी देशों तक विस्तारित किया गया जिन्हें केंद्र और परिधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता

था। केंद्र में ऐसे देशों का समावेश है जहाँ विनिर्माण का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है जबकि परिधि देश ऐसे हैं जो मुख्यतः कृषि वस्तुओं और कच्चे माल को अपने देश से बाहर भेजते हैं अर्थात् उनका निर्यात करते हैं और इनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। केंद्र अर्थात् प्रमुख देश प्राथमिक माल को मांगने पर लगने वाली लागत की तुलना में जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं, ऐसी वस्तुओं से अधिक मुनाफा कमाते हैं। केंद्र को जाने वाली बचत को अपने पास बनाए रखने के योग्य होता है क्योंकि विकसित संघों और वाणिज्यिक संस्थाओं के माध्यम से यह अधिक मुनाफा और उच्च वेतन को बनाए रख सकता है। परिधि देशों में अर्थात् केंद्र देश के इर्द-गिर्द के देशों की कंपनियां और कामगार दुर्बल होते हैं और निम्न कीमतों के रूप में इन्हें अपनी तकनीकी बचत को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है। प्रेबिश ने औद्योगिक और गैर-औद्योगिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को ध्यान में रखकर पतन की ओर इशारा किया जिसका अर्थ था कि परिधि राष्ट्रों को औद्योगिक निर्यात की समान कीमत वसूलने के लिए और अधिक निर्यात करना पड़ता था। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे फायदे केंद्र देशों को मिलेंगे (वही)।

इस स्थिति पर प्रेबिश का समाधान था कि निर्धन परिधि देशों को समृद्ध राष्ट्रों की विनिर्मित वस्तुओं को अपने देश में मांगने पर रोक लगानी होगी और आयात स्थानापन्न की खोज करनी होगी और इस तरह अपनी उपयोगी विदेशी मुद्रा की बचत करनी होगी। प्रेबिश द्वारा निकाला गया हल एकदम स्पष्ट था : निर्धन राष्ट्रों को आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को शुरू करना होगा। ताकि उन्हें समृद्ध देशों के विनिर्मित उत्पादों की खरीद करने की जरूरत न पड़े। निर्धन देश अभी भी विश्व बाजार में अपने प्राथमिक उत्पादों की बिक्री करते रहेंगे, लेकिन उनकी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रयोग मुख्य देश की निर्मित सामग्री को खरीदने के लिए नहीं किया जायेगा। इसका अर्थ था कि घरेलू बाजार को विनिर्मित वस्तुओं की मांग की पूरा करने के लिए विकसित करना ही होगा। इसका यह भी अर्थ था कि सरकारों को आयात को घटाना होगा। इस दावे ने बहुत सी शंकाओं को भी उभारा कि क्या व्यवहारिकता में ऐसा कर पाना संभव है क्योंकि इसके लिए विनिर्माण की दृष्टि से भी देश को मजबूत होने की जरूरत है जिससे कि कीमते निम्न रहें लेकिन जो कि निर्धन राष्ट्रों में नजर नहीं आ रहा था। प्रेबिश का शोध कार्य और निष्पत्ति काफी लोकप्रिय हो गई और केंद्र और परिधि और आयात स्थानापन्न के मूल शोध में बहुत से अन्य विचारकों के सुझाव भी जुड़ने लगे। 1960 में 1970 के समय में गंडर फ्रैंक और इमैनुअल वालरस्टेन ने व्यापार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए आगे इस शोध कार्य का विस्तार किया। आगामी अनुभाग में हमें गंडर फ्रैंक और वालरस्टेन के प्रमुख विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे।

### चिंतन एवं कार्रवाई 9.1

आयात स्थानापन्न से आप क्या समझते हैं? रॉल प्रेबिश द्वारा प्रचारित आश्रयता सिद्धांत के मूल सार की संक्षेप में चर्चा करें।

### 9.3 आश्रयता सिद्धांत का विस्तार: गंडर फ्रैंक एवं वालरस्टेन

गंडर फ्रैंक ने प्रेबिश की मूल अभिधारणा का व्यापार की विस्तृत राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक बढ़ाया। वह अनिवार्यतया मार्क्सवादी था जिसने पूंजीवादी ढाँचे में निहित राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता संबंधों के मूल बिंदु से समृद्ध और निर्धन राष्ट्रों के बीच की दूरी को देखा। प्रेबिश द्वारा प्रतिपादित आश्रय की कुछ आरंभिक संकल्पनाओं को गंडर फ्रैंक ने आगे बढ़ाया जैसे कि केंद्र-परिधि संकल्पना का गंडर फ्रैंक ने आगे विस्तार किया और इन्हें उपाश्रित और साम्राज्यिक राष्ट्रों के नाम दिए। जहाँ आश्रयता की प्रारंभिक संकल्पना राजनीतिक आर्थिक

विश्लेषण की ओर उन्मुख था, वह मुख्यतया आर्थिक संबंधों पर केंद्रित थी। गंडर फ्रैंक ने हेनरिक कारडोसो और थियोटोनियों डोस सैन्टोस जैसे बहुत से अन्य विचारकों ने अपने विश्लेषण को सामाजिक दशाओं विशेष रूप से वर्ग संरचना और प्रादेशिक असमानता और आंतरिक उपनिवेशवाद तक विस्तारित किया। इस अनुभाग में हम गंडर फ्रैंक और वालरस्टेन की रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे यद्यपि इनके अलावा और भी बहुत से सिद्धांतवादियों ने तीसरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य से सामान्य आश्रयता और अल्पविकास आधारित वादविवाद को समझने में अपना योगदान दिया है।

### आन्द्रे गंडर फ्रैंक

गंडर फ्रैंक के मूल विचारों को समझने से पहले आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर प्रकाश डालें।

#### बॉक्स 9.2 आन्द्रे गंडर फ्रैंक

जर्मनी में जन्में फ्रैंक की शिक्षा-दीक्षा स्वित्जरलैंड में पूरी हुई थी। जब अडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने तो फ्रैंक परिवार 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ बसा। फ्रैंक ने शिकागो विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था 1928-1955 के समय में यूक्रेनियन कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता। उन्होंने 1950 से 60 तक के दशक में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। 1962 में उन्होंने लेटिन अमेरिका की ओर रुख कर लिया जहाँ उन्होंने चिली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शिक्षा प्रदान की। यहाँ वे सलवोदोर अलेंदे की अगुआई में सरकारी सुधारों के क्षेत्र में जुट गए। जब अलेंदे सरकार का तख्ता पलटा तो फ्रैंक चिली छोड़ यूरोप जा बसे। फ्रैंक ने बहुत से विषयों जैसे मानव शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास की शिक्षा दी और ऐसे ही बहुत से विभागों में काम किया। उन्होंने बहुत से विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जिनमें से नौ विश्वविद्यालय उत्तर अमेरिका में, तीन लेटिन अमेरिका में और पांच यूरोप में हैं। उन्होंने विश्व भर के दर्जनों विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, इतालवी, जर्मनी और डच भाषाओं में अनगिनत व्याख्यान दिए और अन्य संस्थानों में आयोजित सेमिनारों में भाग लिया। फ्रैंक में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास, विश्व व्यवस्था के समकालीन विकास, औद्योगिक रूप से विकसित देश और विशेष रूप से तीसरी दुनिया और लेटिन अमेरिका पर लिखा, 30 से अधिक भाषाओं में उनकी 1000 से अधिक रचनाएं हैं। अपने नवीन कार्यों में उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न संकट और वैश्विक विश्व इतिहास के विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

(स्रोत: <http://en.wikipedia.org/8/wiki/Gunder-Frank>)

फ्रैंक, आरंभ में विकास के प्रति नव-उदारवादी उपागमों के आलोचक थे। इस उपागम के अनुसार अविकसित देश काफी पीछे हो गए थे और सामन्तवाद के चुंगल में फंसे हुए थे और जिससे उन्हें बाहर निकलने की जरूरत थी। फ्रैंक इस विचार के विरुद्ध थे और आधुनिकीकरण और प्रगति के विचार के भी विरुद्ध थे जो कि विकास के वृद्धि मॉडलों का अभिन्न भाग था। उन्होंने दोहरे समाज शोध पर कड़ा एतराज जताया जिसका दावा है कि अल्पविकास से सामन्तवाद प्रथा का दर्शाना है और इसमें आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अल्पविकास को विश्व पूंजीवाद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो कि पूर्व व्याप्त सामंती व्यवस्था का रूपांतर करता है और इनके अधिशेष का प्रयोग जिसने विकसित राष्ट्रों के फायदे के लिए किया। फ्रैंक के सिद्धांत में अल्पविकास कोई असली दशा नहीं है और न ही यह एकाकी क्षेत्रों में चल रही पुरातन संस्थाओं की उपज है बल्कि

यह तो उसी समान प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जो केंद्र को विकसित करती हैं (विशेष रूप से परिधि देशों में, अल्पविकास वहाँ अधिशेष के खत्म हो जाने से उत्पन्न होता है जिसे कि केंद्र देशों में निवेश के लिए हरण कर लिया जाता है।

आन्द्रे गंडर फ्रैंक, इस बिंदु पर पूरी तरह स्पष्ट है "ऐतिहासिक शोध दर्शाते हैं कि समकालीन अल्पविकास मुख्य रूप से उपाश्रित अल्पविकसित और अब विकसित सामाजिक देशों के बीच पिछले ऐतिहासिक संबंधों और साथ ही साथ बनने वाले नये आर्थिक एवं अन्य किस्म के संबंधों का नतीजा है। इसके अलावा ये संबंध समग्र रूप से वैश्विक पैमाने पर पूँजीवाद व्यवस्था का अनिवार्य भाग है" (फ्रैंक 1972 : 3)।

मार्क्सवादी नजरिए से जैसे कि फ्रैंक के नजरिए से पूँजीवाद व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन को उत्पन्न किया है जो कि विश्व के बहुत से क्षेत्रों में अल्पविकास के लिए उत्तरदायी है। पर निर्भर राज्य या परिधि राज्य सस्ते खनिज, कृषि वस्तुएं और सस्ते श्रम जैसी सस्ती प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करते हैं और अधिशेष पूँजी, पुरानी प्रौद्योगिकी और विनिर्मित वस्तुओं की खान या भंडार के रूप में भी समृद्ध देशों की सेवा करते हैं। ऐसे कार्यों से निर्भर राज्यों की आर्थिक व्यवस्था बाहर की ओर रुख कर लेती है: धन, वस्तुएं और सेवाएं पर निर्भर राज्यों में अपना प्रवाह कायम तो करती हैं, लेकिन इन संसाधनों के आबंटन का निर्धारण पर निर्भर राज्यों के आर्थिक हितों की तुलना में प्रबल राज्यों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। श्रम का यह विभाजन अंततः निर्धनता को स्पष्ट करता है और सवालिया निशान लगाता है लेकिन पूँजीवाद इस श्रम विभाजन के संसाधनों के सक्षम आबंटन की अनिवार्य शर्त के रूप में देखता है। इस विशेषता से जो बात बिल्कुल साफ नजर आती है वह तुलनात्मक फायदे के सिद्धांत में निहित है"। (फेरारो 96: 4, [www.mtholyope.edu/acd/intere/depend.htm](http://www.mtholyope.edu/acd/intere/depend.htm))।

गंडर फ्रैंक द्वारा प्रतिपादित आश्रयता सिद्धांत का सार पूँजीवादी विश्व व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है और जिसे वह असमान विकास के लिए उत्तरदायी मुख्य बल के रूप में देखता है और यह बात इस अवधारणा पर टिकी हुई है कि राजनीतिक और आर्थिक ताकतें मोटे तौर पर उद्योगीकृत देशों में जमी हुई हैं और वहाँ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आइए अब इमैन्युअल वालरस्टेन की ओर रुख करें।

### इमैन्युअल वालरस्टेन

1960 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार व्यवस्थाएं अधिक लचीली होनी शुरू हो गई थी और जिसमें राष्ट्रीय सरकारों का प्रभाव कम से कम नजर आने लगा था। ये ऐसी नयी दशाएं थी जिनके अंतर्गत तीसरी दुनिया के देश अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे थे। यही वह बात थी जिसने इमैन्युअल वालरस्टेन जैसे विचारकों को यह निष्कर्ष देने को कहा कि पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था में नयी गतिविधियों की शुरुआत है और जिन्हें पुराने सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया जा सका।

इस मत की स्थापना मूल रूप से न्यूयार्क राज्य विश्वविद्यालय, बिंघमटन में फरनद ब्राऊडल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इकनोमिक्स में हुई। मूल रूप से इसका संबंध समाजशास्त्र से था लेकिन इसने अपने प्रभाव का विस्तार मानवशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तक किया। वालरस्टेन और इसके मानने वालों ने महसूस किया कि विश्व में विस्तृत बल थे जिनका छोटे और अल्पविकसित देशों पर प्रभाव पड़ा और अल्पविकसित देशों की दशाओं को स्पष्ट करने में राष्ट्र-राज्य स्तर का विश्लेषण और अधिक उपयोगी नहीं है। छोटे देशों पर जिन कारकों का सर्वाधिक प्रभाव था, वे थीं संचार की नयी वैश्विक व्यवस्थाएं, नव विश्व व्यापार तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था और सैन्य संबंधों का अंतरण। इन कारकों ने अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर स्वयं अपनी गतिशीलता को सृजित किया है और साथ ही साथ ये मूल तत्व प्रत्येक देश के अंदरूनी पहलुओं से भी अंतःक्रिया कर रहे हैं। यद्यपि इमैन्युअल वालरस्टेन आश्रयता सिद्धांत के आलोचक हैं और इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। दूसरों की भांति वे भी ऐसी आर्थिक हानियों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जिनका सामना देश या क्षेत्र को विस्तृत वैश्विक व्यवस्था के भाग के रूप में करना पड़ता है। वालरस्टेन के 1987 के विश्व व्यवस्था विश्लेषण पर प्रकाशित अभिलेख में वे प्रमाणित करते हैं कि विश्व-व्यवस्था सिद्धांत ऐसे तरीके का विरोध करता है जिसमें 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी शुरुआत पर हम सभी के लिए सामाजिक वैज्ञानिक जाँच संरचित हैं। वे आश्रयता सिद्धांत की मौजूदा संकल्पना की आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका तर्क है कि विश्व इतना जटिल है कि इसे केंद्र, देश और परिधि देश जैसी व्यवस्थाओं में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस बात के मद्देनजर विश्व-व्यवस्था सिद्धांत के एक मुख्य सिद्धांत पर नजर पड़ती है अर्थात् अर्थ-परिधि संकल्पना पर विश्वास करना जिसने त्रिकोणीय व्यवस्था को उत्पन्न किया जिसमें केंद्र, अर्थ-परिधि और परिधि राष्ट्रों का पता चलता है (स्रोत : [http://11.en.wikipedia.org/80/wiki/World System Theory](http://11.en.wikipedia.org/80/wiki/World_System_Theory))

### बॉक्स 9.3: इमैन्युअल वालरस्टेन

न्यूयार्क में जन्में, वालरस्टेन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहाँ से उन्होंने 1951 में बी.ए. की उपाधि और 1954 में एम.ए. की और 1959 में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की और तत्पश्चात् 1971 तक वहाँ उन्होंने लेक्चरर का कार्य मैकमिल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रोफेसर बनने तक किया। 1999 में सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने बिंघमरन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। सेवानिवृत्ति के समय वालरस्टेन फरनंद बरूडल सेंटर फार द स्टडि ऑफ इकनोमिक्स के विभागाध्यक्ष भी थे। उन्होंने बहुत से पदों पर काम किया जैसे यूनिवर्सिटीज वर्ल्डवाइड में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्हें मल्टीपल हौनैरेटी टाइटलों से नवाजा गया। 1994 से 1998 तक आप अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के अध्यक्ष थे। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974, 1980 और 1989 में तीन खंडों में नजर आया। इन खंडों में वालरस्टेन मुख्य रूप से तीन बुद्धिजीवियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

- 1) कार्ल मार्क्स जिनका अनुसरण, वे निहित आर्थिक कारकों पर जोर देते समय और वैश्विक राजनीति में सैद्धांतिक कारकों पर इनका वर्चस्व कायम होता देख कर करते हैं।
- 2) फ्रांसीसी इतिहासकार फरनंद ब्राउडल जिसने पुरकाल के विस्तृत साम्राज्य के संदर्भ में विकास और आर्थिक विनिमय के विस्तृत नेटवर्कों के राजनीतिक निहितार्थों को स्पष्ट किया था; और
- 3) अफ्रीका में उपनिवेशवाद के बाद के समय में अपने खुद के कार्य से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव और प्रभाव और 'विकासशील राष्ट्रों' पर ध्यान केंद्रित करने वाले बहुत से सिद्धांतों से अर्जित ज्ञान।

(स्रोत : [http://11.en.wikipedia.org/80/wiki/Immanuel Wallerstein](http://11.en.wikipedia.org/80/wiki/Immanuel_Wallerstein))

आधुनिकीकरण और पूँजीवाद के अन्य सिद्धांतवादियों की तुलना में वह केंद्र, अर्थ-परिधि और परिधि विभाजनों को विश्वव्यवस्था के चिरस्थायी विभाजन, मानते हुए कहता है कि ये विभाजन कोई अवशिष्ट या ऐसी अनियमितता नहीं हैं जो दूर हो जायेगी। वह इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखता है और 16वीं शताब्दी, आरंभिक पूँजीवदी संचयन और धीरे-धीरे आगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दौरान इसका विस्तार देखता है। उसके अनुसार पूँजीवादी विश्वव्यवस्था सजातीयता से काफी अलग है और देश या क्षेत्र के नागरिक संबंधी विकास

को ध्यान में रखकर पूँजीवादी संचयन और राजनीतिक सत्ता में असमानाएँ पाई जाती हैं। वालरस्टेन की नज़र में पूँजीवाद विश्वव्यवस्था गतिशील व्यवस्था है जो निश्चित समयावधि के बाद बदल जाती है। हालांकि इसकी कुछ बुनियादी विशेषताएँ एक सी ही रहती हैं। केंद्र या पश्चिमी यूरोपियाई देश और अन्य विकसित राष्ट्र मुख्यता परिधि देशों से कच्चे माल के लिए विनिर्मित वस्तुओं के विनिमय से अर्जित उच्च मुनाफे के माध्यम से विश्व पूँजीवादी व्यवस्था से फायदा उठाते रहे। वालरस्टेन का विश्लेषण सत्ता की राजनीति और अंदरूनी गतिशीलता को भी इस संदर्भ में ध्यान में रखते हैं। परिधि देशों में उदाहरणार्थ भूपत्ति अक्सर दुर्बल या लाचार श्रमिकों से कम पैसे में काम करवा कर उनकी मेहनत हड़प कर अधिक संपत्ति कमाते थे क्योंकि भूपत्ति अपने श्रमिकों की अतिरिक्त मेहनत को अपने लाभ के लिए छीनने के योग्य थे जिसके परिणामस्वरूप मुख्य क्षेत्रों में बहुत से मूल ग्रामीण जो धीरे-धीरे भूमिहीन बनने लगे थे उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया जिससे उनका जीवन स्तर घटने लगा और उनकी आमदनी की निश्चितता लुप्त होने लगी। समग्र रूप से वालरस्टेन पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था के विकास को विश्व की आबादी के बड़े भाग के लिए हानिकार मानते हैं।

विश्वव्यवस्था सिद्धांत को मानने वालों द्वारा मुख्य और परिधि और अर्ध-परिधि देशों के बीच के सत्ता संबंधों के मद्देनजर चीन और ब्राजील जैसे अर्ध-परिधि देशों के उदय को स्पष्ट करने के लिए उजागर किया गया है। वालरस्टेन की पूँजीवादी विश्वव्यवस्था की आलोचना करने के लिए उन्हें बहुत से वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों में लोकप्रियता हासिल हुई। अन्य बातों के अलावा उसकी आलोचना ने इतिहास के निर्मूल विश्लेषण के लिए उसे गलत ठहराया है और आमतौर पर जिस अंदाज में वे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर बात करता है।

अभी तक हमने आश्रयता सिद्धांत की तीन लड़ियों को समझने का प्रयास किया है जिन्हें जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था कि यह न केवल विकास के नव उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना है बल्कि व्यापार को अलग-थलग होकर न कर पाने के रूप में भी देखती हैं लेकिन इस संदर्भ में यह राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से विश्वव्यवस्था पर गौर करती है। आगामी अनुभाग में हम आश्रयता सिद्धांत की मुख्य प्रतिज्ञप्तियों पर पकड़ कायम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए बॉक्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

### चिंतन एवं कार्रवाई 9.2

हमने तर्क-वितर्कों की जिन उपर्युक्त उल्लिखित लड़ियों का अध्ययन किया उसके बाद आप अवश्य महसूस कर रहे होंगे कि आश्रयता के विचारक अनिवार्यतया इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि विश्व इस तरह से अंतःसंबद्ध है कि विकास या अल्पविकास को एकाकी रूप से नहीं देखा जा सकता है। इस बात के मद्देनजर:

- 1) क्या आप कहेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्वीकरण की दृष्टि से विश्व के वैश्विक ग्राम बनने से विश्व केंद्र और परिधि देशों जैसी संकल्पना में बंट गया है?
- 2) यदि आपको विश्वव्यवस्था सिद्धांत के नजरिए से तर्क-वितर्क करना है जो आप भारत को परिधि राष्ट्र मानते हैं या अर्ध-परिधि राष्ट्र?

## 9.4 आश्रयता सिद्धांत की अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियाँ

आश्रयता के विचारकों का कुछ बातों पर आपसी तालमेल है लेकिन कुछ बातों पर वे एक-दूसरे से सहमत नहीं भी होते। संकल की परिभाषा कुछ हद तक आश्रयता सिद्धांत का सार है।

उसका कहना है कि राष्ट्रीय विकास नीतियों पर देश के बाहरी प्रभावों-राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का जो प्रभाव पड़ता है उस दृष्टि से देश के आर्थिक विकास का स्पष्टीकरण आश्रयता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है" (संकल 1969 : 23)। आन्द्रे गंडर फ्रैंक, पॉल बरन और हेनरिक कारडोसो जैसे सिद्धांतवादियों की इस बात पर सहमति है कि विकसित विश्व के देश तेजी से एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं और उनके विचार में यह संबंध उस संबंध से अलग है जो विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच होता है। बैंकर और ग्राहक भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं क्योंकि बैंकर को अपनी उत्तरजीविता कायम रखने के लिए ऋण देकर आमदनी बनाने की जरूरत है और दूसरी तरफ ग्राहक को अपना घर बनाने के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस संबंध की संरचना एकदम असमान है और यह असमानता उनके बीच की सभी अंतः क्रियाओं को ढक देती है। थियोटोनियो डोस सैनटोस अपनी परिभाषा में आश्रयता सिद्धांतों के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। (आश्रयता है)...ऐसी ऐतिहासिक दशा जो विश्व अर्थव्यवस्था की निश्चित संरचना की रूपरेखा को विकसित करती है जैसे कि इससे कुछ देशों को जहां नुकसान होता है उनके लाभ को हड़प कर यह कुछ देशों को फायदा देती है और अधीनस्थ देशों की विकास संभावनाओं को सीमित करती है...ऐसी स्थिति जिसमें कुछ निश्चित समूह के देशों की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के विकास और विस्तार से जुड़ी होती है। To Which their own is subjected (डेस सैनटोस 1971 : 226)

### आश्रयता सिद्धांत के कुछ प्रमुख दावे :

सभी आश्रयता के विचारक विकास के नव उदारवादी सिद्धांतों के आलोचक हैं जिनका दावा है कि अल्पविकसित राष्ट्रों को आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत करना बाकी है और ठोस आर्थिक व्यवहारों और नीतियों को एक बार जब वे अपना लेंगे तो वे अपनी प्रस्थिति से उबर जायेंगे। दरअसल, 1950 और 1960 के दौरान निर्देशनात्मक सर्वसम्मति थी कि वृद्धि रणनीतियों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। इस सर्वसम्मति को वाल्ट रेस्तो ने अपनी पुस्तक द स्टेजिस ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ में श्रेष्ठ रूप से स्पष्ट किया है। आश्रयता सिद्धांत की राय है कि समृद्ध देशों की सफलता अत्यंत पर निर्भर है और वैश्विक इतिहास के विशिष्ट प्रसंग में यूरोपियाई सत्ताओं के अत्यंत शोषणकारी औपनिवेशिक संबंधों का काफी वर्चस्व था। इन संबंधों की पुनरावृत्ति अब आज के समय में विश्व के गरीब देशों के लिए वैसी प्रबल नहीं है। आश्रयता सिद्धांत नवक्लासिकी मॉडल के केंद्रीय वितरणकारी तंत्र को परित्यक्त करती है जिसे आमतौर पर 'ट्रिकल डाउन' अर्थशास्त्र कहते हैं। आश्रयता के विचारक बहुत से ऐसे संरचनागत तत्वों की जांच करते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की असफलता के लिए उत्तरदायी माना जाता है जैसे जातीय, नृजातीय या जेंडर पूर्वाग्रह आदि। ऐसे संरचनागत कारणों के लिए आश्रयता सिद्धांतवादियों का तर्क है कि बाजार अकेले ही पर्याप्त वितरणकारी तंत्र नहीं है (फेरारो, 1996 स्रोत: [www.intholyoke.edu/acad/intre/dpend](http://www.intholyoke.edu/acad/intre/dpend))। एक अन्य प्रतिज्ञप्ति जिसे कि आश्रयता सिद्धांत के लिए सामान्य माना जाता है : विश्व का केंद्र/परिधि/उपाश्रित सामंज्यिक और केंद्र/अर्धपरिधि रूप से विभाजन। केंद्र देश पश्चिमी के उन्नत देश हैं जो अनिवार्यतया अधिक जटिल वस्तुओं का निर्माण करते हैं और जिनका निर्यात केंद्र देशों को किया जाता है। परिधि देश निर्धन राष्ट्र हैं जो कृषीय उत्पादों और कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राथमिक उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। ये अमीर राष्ट्रों के लिए सस्ते श्रमिक और बाजारों का भी बंदोबस्त करते हैं।

इन सभी सिद्धांतों में निहित आम अवधारणा है कि परनिर्भर राष्ट्र प्रौद्योगिकों के अभाव या सामंतवाद जैसे व्यवहारों के अभी भी मौजूद होने के कारण निर्धन नहीं हैं बल्कि असल में जर्बदस्ती इन्हें यूरोपियाई आर्थिक व्यवस्था में समेकित किया गया। ये मुख्य रूप से कच्चे माल के उत्पादक या सस्ते श्रम की खान ही बन कर रह गए और इन्हें ऐसे बाजारों से अपने



संसाधनों को ले जाने के अवसरों से वंचित कर दिया गया जो प्रबल राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कायम किए हुए थे। परिधि राष्ट्र संरचित असमानता के संबंध में केंद्र राष्ट्रों पर निर्भर हैं और इन्हें ऐसी व्यवस्था में विकसित किया जाता है जो कि पहले से ही विकसित राष्ट्रों द्वारा बसाई गई है जिससे परिधि राष्ट्रों का क्रमबद्ध हानि का सामना करना ही पड़ता है। अंतःक्रिया करने वाले राष्ट्रों के बीच सत्ता के असीमित संबंधों के कारण यह अंतःनिर्भरता से भिन्न है।

- बाहरी बलों का आश्रयता सिद्धांतवादियों का तर्क है कि राष्ट्र के अल्पविकास में भारी भूमिका है। इस बात पर वे सभी सहमत हैं कि परनिर्भर राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए बाहरी बलों का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसे बाहरी बलों में शामिल हैं : बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार, विदेशी सहायता, संचार और ऐसे अन्य साधन जिनके माध्यम से उच्च उद्योगीकृत देश अपने आर्थिक... हित... विदेश को दर्शा सकते हैं (फेरारो 1996, स्रोत [www.mtholyoke.edu/acod/intrel/depend](http://www.mtholyoke.edu/acod/intrel/depend))।

- निश्चित समय में संसाधनों का रुख मोड़ना (और याद रहे कि परनिर्भरता के संबंधों की निरंतरता पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोपियाई विस्तार की शुरुआत से बनी हुई है)

सिर्फ प्रबल राज्यों की ताकत से ही कायम नहीं है बल्कि परनिर्भर राज्यों के कुलीन वर्ग की सत्ता के माध्यम से भी यह असमानता बनी हुई है। आश्रयता के विचारकों का तर्क है कि इन कुलीनों ने परनिर्भर संबंध कायम रखा क्योंकि इनके अपने निजी हित प्रबल राज्यों के हितों के समान थे। इन कुलीनों को प्रबल राज्यों में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था और प्रबल राज्यों के कुलीनों की सोच जैसी ही इनकी सोच थी और इनके मूल्य और संस्कृति भी एक जैसी ही थी। अतः सही मायने में परनिर्भरता संबंध 'सवैच्छिक' संबंध है। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि परनिर्भर राज्य सोच समझकर अपने निर्धनों के हितों से धोखा कर रहे हैं, कुलीनों का सही रूप से मानना है कि आर्थिक विकास की कुंजी उदारवादी आर्थिक सिद्धांत के निम्नलिखित आदेश में निहित है (वही)।

- आत्म-निर्भरता और घरेलू बाजार की सुरक्षा को सहज शोषणकारी विश्व व्यवस्था से बाजार रहने के महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा गया। प्रेबिश जैसे सिद्धांतवादियों के आयात स्थानापन्न जैसी विषयवस्तुओं पर विशिष्ट विचार हैं, जबकि कुछ अन्य सिद्धांतवादियों के राज्य की भूमिका और घरेलू हित को सुरक्षित रखने पर अपने तर्क पेश किए। उनका मानना है कि श्रेष्ठ रूप से देश के राष्ट्रीय हित की सुरक्षा उसी देश के निर्धनों की सेवा करके की जाती है और इसके बाद बाहरी एजेंसियों की मांग का अनुसरण करके। राष्ट्रीय हित आखिरकार किससे बनता है या व्यावहारिकता में इसका क्या अर्थ है, इस बात पर स्पष्ट रूप से बहस नहीं की जाती।

अतः सामान्य रूप से आश्रयता का सिद्धांत विकास की स्वीकृति धारणाओं की आलोचना थी जो कि मूल रूप से मुख्यतया यूरोपियाई राष्ट्रों के बढ़ते वर्चस्व और उनके हितों से जुड़े हुए थे। आश्रयता के सिद्धांत इसलिए बहुत से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में काफी लोकप्रिय हैं और कुछ ऐसी राजनीति तक पहुंचने का प्रयास करते तो हैं जो उनके देशों के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन इनके काफी आलोचक भी हैं। हमने इसके आलोचनात्मक पहलुओं में कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष चिंतन की जांच नहीं की है लेकिन अपने अगले अनुभाग में हम कुछ समीक्षाओं पर नजर डालेंगे।

### चिंतन एवं कार्रवाई 9.3

विकासशील देश/देशों का आर्थिक पिछड़ापन स्पष्ट करने में आश्रयता सिद्धांत की अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियों की आलोचनात्मक जांच कीजिए।

## 9.5 आश्रयता सिद्धांत की समीक्षा

वृद्धि मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आश्रयता सिद्धांत ने वैक्लिपिक उपागम प्रदान किया है। उन्होंने ऐसे देशों के सतत असमान संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है जिनका आधा इतिहास उपनिवेशवाद में और आधा साम्राज्यवाद में बंटा हुआ है। जब आश्रयता सिद्धांतों ने उत्तर के बारे में दक्षिण से वेल्कम समीक्षा प्रदान की है तो इनमें कुछ दोष और आलोचना का भी समावेश था। आश्रयता सिद्धांतों की प्रमुख आलोचना रही है कि ये सिद्धांतवादी अपने तर्कों का महत्व देने के लिए कोई ठोस प्रमाणों को पेश नहीं करते। ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं लेकिन बहुत से अपवाद हैं जो केंद्र परिधि सिद्धांतों में सही ढंग से फिट नहीं बैठते जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के नव उदित औद्योगिक देश।

यह भी कहा गया है कि आश्रयता सिद्धांत अत्यधिक अमूर्त है और विकसित और अल्पविकसित जैसी सजातिक श्रेणियों का प्रयोग करने की ओर प्रवृत्त है जिससे कि इन श्रेणियों में निहित असमानता पर पूरी तरह पकड़ नहीं बन पाती।

आलोचना का अन्य बिंदु है कि आश्रयता का सिद्धांत बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंध कायम रखने को हानिकर मानता है जबकि एक नजरिया यह भी रहा है कि ये प्रौद्योगिकी अंतरण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आश्रयता सिद्धांत की अन्य आलोचना हैं ये राज्य, पूंजीवादी, उद्योगीकरण जैसे शब्दों पर अपने तर्कों को टिकाते हैं। आश्रयता मत के इन विचारों में कुछ यूरोसेन्द्रीक पूर्वाग्रहों को निहित किया गया है जैसे ये मान कर चलते हैं कि औद्योगिकीकरण और औद्योगिक पूंजी का स्वामित्व आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षित बिंदु हैं। इसने राज्य का विकास एकमात्र अभिकर्ता के रूप में पुनर्गठित कर दिया है। दरअसल, आर्थिक विकास के प्राथमिक और अनिवार्य एजेंट के रूप में राज्य पर इससे परे हट कर विचार करने में यह अयोग्य है। इन सिद्धांतवादियों ने आगे विकास को आर्थिक दृष्टि से देखा है। विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम स्पष्ट रूप से इनके तर्कों से गायब हैं। आश्रयता सिद्धांतों की एक विशेष आलोचना है कि ये समकालीन विश्व की परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों के प्रतिबिम्बित नहीं करते। बहुत सी समीक्षाएं न्यायसंगत हैं और हमें जो बात स्वयं से पूछनी है, वह है कि क्या आश्रयता सिद्धांत के पीछे के अनिवार्य विचार और विचारधारा की मौजूदा संदर्भ में कोई प्रासंगिकता है। आइए आगामी अनुभाग में इस बात पर चर्चा करें।

## 9.6 आश्रयता सिद्धांत की प्रासंगिकता

बढ़ते वैश्वीकरण ने जो कि अनिवार्य सामाजिक शर्त और प्रक्रिया के रूप में नजर आता है, ने आज के समय में विश्व के अंतःसंबद्ध प्रकृति की ओर इशारा किया है। विश्व भर में पूंजी, वित्त, वस्तुओं, जन और विचारों का इतना प्रवाह पहले कभी नहीं रहा। ऐसे कुछ अंतःसंबंध की ओर 1950 में ई.सी.एल.ए.सी. ने और बाद में आश्रयता के सिद्धांतवादियों और विश्वव्यवस्था विचारकों ने इशारा किया। दोनों सिद्धांत वैश्विक संदर्भ में अल्पविकास और विकास की समस्याओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रमों के अंतःसंबंधों के रूप में देखते हैं। आश्रयता सिद्धांत का पूर्वानुमान है कि विश्वव्यवस्था कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय निगमों के हाथों में उत्पादन का जिम्मा सौंपने का विश्व को अल्पाधिकार उन्मुख बाजार बनाने की ओर प्रवृत्त है। इससे सिद्धांत उत्पादन में मंदी करने और आमदनी धुवण को तेज करने के लिए लंबी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान भी लगता है'' (स्रोत: राबिन्सन रोजस, [www.rojasdatabank.org](http://www.rojasdatabank.org).)।

उद्योगिकृत देशों और विकासशील देशों के बीच आर्थिक विभाजन और आमदनी अंतराल निरंतर विस्तृत हो रहा है। उत्तर और दक्षिण के बीच का ध्रुवीकरण अब जितना स्पष्ट है

इतना पहले कभी नहीं रहा। 1997 की संयुक्त राष्ट्र मानव रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व आबादी के कुल 10 प्रतिशत के रूप में 48 न्यूनतम विकसित राष्ट्रों के लिए विश्व व्यापार का अंश पिछले दो दशकों में दो भागों में बंट गया है। जैसा कि इन आंकड़ों में दर्शाया गया है अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच विस्तृत अंतराल है। विश्व के लोगों के निर्धनतम 20 प्रतिशत की वैश्विक आमदनी 1960 में 2.3 प्रतिशत और 1991 में 1.4 प्रतिशत से घट कर 1.1 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर पहुंच गई है जबकि उन निर्धनतम 20 प्रतिशत की तुलना में सर्वोच्च धनियों के 20 प्रतिशत की आमदनी 1960 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 60 प्रतिशत के अनुपात पर पहुंच गई और 1944 तक बढ़कर यह 78:1 हो गई थी। अन्य शब्दों में अमीर और अधिक अमीर हो रहे थे जबकि गरीब और अधिक गरीब बन रहे थे।

“इन प्रवृत्तियों के कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, जबकि मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है ये केवल वैश्विक आय का 1 प्रतिशत और समग्र रूप से राष्ट्रीय आय का 2-3 प्रतिशत भाग ही लेगी। ये संख्याएं इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि लोगों और राष्ट्रों के बीच बढ़ती इस असमानता पर ध्यान देना और इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है” (यू.एन.डी.पी. 2001)

यह सही है कि हम अंतःसंबद्ध विश्व में रहते हैं। अपने तर्काधारों के लिए आश्रयता सिद्धांतों की जांच करने का कारण है यद्यपि इन्हें देखते हुए नहीं लगता कि ये समकालीन परिस्थितियों और स्थितियों पर अपना प्रभाव डालती है और इनके कुछ सूत्रीकरणों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। हालांकि बढ़ते अंतःसंबद्ध अर्थशास्त्रों और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इन सिद्धांतों की आलोचनात्मक जांच करना बेहतर होगा।

तालिका 9.1:

156 बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुल जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में एस.जी.डी.पी.

	1960	1970	1980	1990	1999
उद्योगीकृत देश (21)	83.2	83.2	78.4	83.3	84.3
उप-सहाराई अफ्रीका (50)	2.5	2.3	2.8	1.4	1.1
दक्षिण एशिया (8)	3.9	3.1	2.2	2.0	2.3
मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका (9)	1.8	2.6	5.5	3.1	1.8
लेटिन अमेरिका और कैरिबियन (41)	6.7	6.8	7.7	5.9	6.7
पूर्व एशिया और प्रशांत (27)	2.0	2.1	3.3	4.4	3.8

स्रोत: विश्व विकास सूचक और विश्व विकास रिपोर्ट

### चिंतन एवं कार्रवाई 9.2

- 1) क्या आपकी राय में राष्ट्र में अंदरूनी असमानता को स्पष्ट करने में आश्रयता सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है?
- 2) अधिकांश विकास के विचारकों का मानना है कि राष्ट्र के विकास के लिए राज्य हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप उनके साथ सहमत हैं?
- 3) क्या आपकी राय में आई एस एफ और विश्व बैंक जैसे सशक्त बहुराष्ट्रीय निगम और एजेंसिया जो कि राज्य नीतियों को प्रभावित करने के लिए जानी जाती हैं, राज्य की भूमिका के महत्व को कम करती हैं?

अपनी पद्धति और परिभाषा से संबंधित सभी कमियों के बावजूद आश्रयता सिद्धांत को बहुत से कम विकसित देशों के हाल ही के ऐतिहासिक अनुभव से इसके महत्व को कम कर दिया गया है। अर्थशास्त्र अकेले ऐसे बहुत से कारकों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति प्रतिबंधित करते हैं। अंतिम विश्लेषण में यदि हम विश्व को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही देखते हैं तो अल्पविकास का अध्ययन अधूरा होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगहों पर राजनीतिक आर्थिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। आश्रयता विश्लेषण सही ढंग से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की अंतःनिर्भरता पर जोर देता है। यदि इनके द्वारा उत्पन्न राजनीतिक-आर्थिक गतिशीलता अक्सर भ्रमित है तो हो कम से कम जिन हवालों का जिक्र होता है वे तो ठीक होने चाहिए। विकास अनुभव के पचास वर्षों के बाद बुद्धिजीवी तेजी से इस बात को उठा रहे हैं कि अल्पविकास आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जैसे कारकों की सम्भ्रान्त व्यूह रचना का परिणाम है। पिछले समय पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि जैसाकि विकास सिद्धांत के प्रवर्तक अल्बर्ट हिर्शमन ने 30 वर्षों पहले लिखा था:

राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध के बारे में सामान्य प्रतिज्ञप्ति लाने का प्रयास करना सिर्फ घिसी-पिटी बात और मायूसी को उत्पन्न करना है। इस स्तर पर संबंधों के लिए ये बातें या तो साफ नजर आती हैं और इसलिए अरोचक होती हैं या इतनी जटिल और परनिर्भर होती हैं कि इसके परिणामों को समझा नहीं जा सकता (1971, 8)। संक्षेप में यह कहना मुश्किल होगा कि किसने आश्रयता सिद्धांत को इतिहास के अंधेरे की ओर धकेल दिया।

वैश्वीकरण का अर्थ है कि लेटिन अमेरिका की आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और साथ ही साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के निष्कासन की चुनौती से जुड़ी हुई हैं। आश्रयता के विचारक पूर्वानुमानित रूप से अपने चिंतन को वैध बनाने के लिए इस अंतर्ज्ञान का प्रयोग का यह दावा करते हुए कहते हैं कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण वित्तीय और मौद्रिक मुद्दों में बहुत सी सरकारों को अपना हाथ आजमाने की प्रक्रिया को प्रतिबद्ध करता है। जहाँ इस बात को मना नहीं किया जा सकता वहीं नीति कार्रवाई की पहले से निम्न स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से विकास के लिए हानिकर नहीं है। असल में बहुत से अर्थशास्त्रियों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों द्वारा विकासशील राष्ट्रों पर थोपे गये नये अनुशासन ने राजनीतिज्ञों के हाथों को बांध कर लापरवाही के सबसे खराब उदाहरणों की छटाई कर दी है। ऐसे वर्तमान से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य से काफी अलग है जब परनिर्भरता सिद्धांतों को 1950 और 1960 के दौरान सर्वप्रथम सूत्रबद्ध किया जा रहा था। लेकिन आगे भी यह लेटिन अमेरिकी सरकार पर है कि वह नए अवसरों का फायदा उठाए और इस नव उदित विश्व आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में पैदा होने वाले नये जोखिमों को सीमाबद्ध करें। इनकी नीतियाँ उन्हें उस सीमा तक उत्तोलक शक्ति देती हैं। जहाँ से वे निजी आर्थिक भाग्य को नियंत्रण करना चाहते हैं। यह अच्छी खबर है कि आश्रयता के सिद्धांत ने अपने अधिक निराशावादी अंदाज में इस संभावना की अनुमति नहीं दी।

## 9.7 सारांश

आश्रयता सिद्धांत विकास के मुख्य सिद्धांत की आलोचना है। संबद्ध समाज की विविध सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता के मद्देनजर बहुत से बुद्धिजीवियों ने इसे स्वीकारा है और बहुतों ने इसे नामंजूर किया है। इस इकाई में हमने इस सिद्धांत की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। सिद्धांत के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए हमने इकाई की शुरुआत की और इसके साथ-साथ फ्रैंक और वालेटरस्टेन द्वारा आरंभ इसके आगे के विस्तार पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र और परिधि और विश्व व्यवस्था जैसे परिप्रेक्ष्यों पर काफी वादविवाद किया गया

है। हमने आश्रयता सिद्धांत की अनिवार्य विशेषताओं की प्रस्तुति की है और साथ ही इस सिद्धांत की आलोचना पर भी प्रकाश डाला है। सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक सामाजिक सिद्धांत की विशिष्ट संदर्भों में अपनी प्रासंगिकता होती है। हमने समकालीन विश्व में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर विचारों की प्रस्तुति की है। हमारा प्रयास यहां कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है बल्कि वैश्वीकरण और विविध अन्य विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में इस सिद्धांत की समीक्षा विकसित करने के लिए कुछ जगह खाली छोड़नी है।

## 9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

लाल, एस. 1975 "इज डिपेंडेंसी ए यूजफूल कान्सेप्ट इन औनालाइजिंग अंडर डेवलपमेंट",  
वर्ल्ड डेवलपमेंट, खंड 3।

फ्रैंक, ए.जी. 1973 "द डेवलपमेंट ऑफ अंडरडेवलपमेंट", इन जेम्स डी. काकक्रोफ्ट (संपा)  
डिपेंडेंसी एंड अंडरडेवलपमेंट। अँकर बुक्स: न्यूयार्क।

यूएनडीपी 2001 मानव विकास रिपोर्ट। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: नई दिल्ली वर्ल्ड बैंक  
2000। विश्व विकास रिपोर्ट। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: नई दिल्ली।